'अदालत' में हारे अरूण जेटली

फ़रीदाबाद (म.मो.) टी.वी. पर रजत शर्मा एक कार्यक्रम पेश करते हैं-आपकी अदालत। वैसे तो यह कार्यक्रम किसी बड़े नेता को बुलाकर उसकी चमचागिरी करने के लिये रखा गया है ताकि सवाल जवाब या आरोप और सफ़ाई के बहाने विभिन्न विषयों पर जनता को यह नेता अपनी सफाई के रूप में भाषण पिला सके। इसके लिये उस नेता को दर्शकों के रूप में अपने समर्थक बुलाने की भी छूट होती है। लेकिन जेटली साहब इसके बावजूद भी इसमें हार गये क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सिर्फ गोलमोल करने के अलावा उनके पास कुछ न था।

जब उनके भाषण के बाद पहले आरोप या सवाल की बारी आयी तो उनसे पूछा गया कि आपने महिला सशक्तिकरण जैसे काम के लिये तो डेढ़ सौ करोड़ रखे है जबकि यह देश की करोड़ों महिलाओं की भलाई का काम है जबकि सिर्फ एक अकेले सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के लिये 200 करोड़ रुपया रखे हैं। इस पर पहले तो जेटली साहब ने सरदार पटेल के गीत गाये कि उन्होंने सभी रजवाड़ों को इस देश में मिलाया जिसके कारण हिन्दुस्तान का वह रूप (यानि वह क्षेत्र) बन सका जिसे आप देख रहे हो। वह यह बताना भूल गये कि पटेल ने ये राज्य फ्री में भारत में नहीं मिलाये थे बल्कि उन सभी राजाओं और नवाबों को प्रिवीपर्स के रूप में इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई में से सालों तक मोटी रकम देते रहे। उपर से उन्होंने अपील भी कर डाली कि इस मूर्ति के लिये तो राज्य सरकारों को भी फंड देना चाहिये। महिलाओं के मुद्दे पर उनके पास कहने को सिर्फ़ इतना ही था कि यह तो एक साल का बजट है पांच साल का नहीं। तो जेटली साहब एक साल के बजट में मूर्ति को भी दस बीस करोड़ रुपये में शुरू किया जा सकता था। बहरहाल दूसरा सवाल ये था कि कांग्रेस के चिदम्बरम ने ये कहा है कि ज्यादातर योजनाओं को सौ-सौ करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं तो ये बजट है ना कि बालीवुड का सौ करोड़िया क्लब! ध्यान रहे कि आजकल बालीवुड में कौन सौ करोड़ रुपया सलाना कमा रहा है उनको सौ करोड़िया क्लब का सदस्य माना जाता है।

इस पर जेटली साहब ने पहले तो खीज कर चिदम्बरम को भला बुरा कहा कि वे वित्तमंत्री रहे हैं और उन्हें समझ होनी चाहिए कि ये बड़ी बड़ी योजनायें है और ये सालों साल में जाकर पूरी होंगी ऐसे में उनके लिये सारा बजट एक ही साल में आवंटित नहीं किया जा सकता। उन्होंने नौएडा का उदाहरण देते हुये कहा कि सालों हो गये लेकिन नौएडा का अभी तक विकास हो ही रहा है। लेकिन महोदय यह सौ करोड़ में नहीं बल्कि हर साल कई सौ करोड़ के बजट में हो रहा है। आप तो कई शहरों में मैट्रो के सपने दिखा रहे हो वह भी सौ करोड़ रुपये में। इतने में तो उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक भी तैयार नहीं होगी। और कुछ तो जाने दीजिए।

इसके बाद श्रोताओं में से एक ने सवाल किया कि सर आपने बचत में छूट की सीमा एक लाख से बढ़ा कर डेढ़ लाख तो कर दी लेकिन हमारी तो सेलरी ही इतनी है कि उसमें गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है, बचत कहां से होगी और इसलिये इस छूट की सीमा बढ़ाने का हमें क्या लाभ होगा। वह नौजवान वास्तव में यह कहना चाह रहा था कि महंगाई के कारण हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा उसका कोई उपाय कीजिये। लेकिन जेटली साहब तो फ़िर वही अपना राग अलापने लगे कि हमने इन्कम टैक्स में छूट बढा दी है, गृह ऋण में छूट बढा दी है आदि-आदि और अन्त में बजाये महंगाई पर बात करने के उसकी सैलरी बढने की शुभकामना देकर जवाब खत्म कर दिया। निश्चित रूप से इन जवाबों से असंतुष्ट दर्शकों ने न तालियां बजानी थी न बजाई।

उधर शशि थरूर के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए तो उन्होंने हद ही कर दी जब इन्होंने 'बिल क्लिंटन' को उद्धृत करते हुए कहा कि 'दिस इज इक्नामिक्स स्टूपिड'। जेटली साहब अभी तो अपने आलोचकों को स्टूपिड कहकर आप उनका मज़ाक उड़ा लीजिए लेकिन परेशान हाल जनता आप का मज़ाक नहीं आप को ही उड़ा कर दूर फ़ेंक देगी। वैसे कूड़ेदान में तो लोकसभा चुनावों में अभी ही जनता ने फेंक दिया था आपको। बहरहाल अपने समर्थकों की बड़ी जमात को दर्शकों में लाने के बावजूद आपके अधिकतर और मुख्य जवाबों पर दर्शकों का तालिया न बजाना उनकी नाराज़गी को दिखाता है और बताता है कि आप मुकदमा हार गये हैं।

राशन विभाग ही कराता कालाबाज़ारी

करनाल:(अशोक) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा के करनाल स्थित कार्यालय के अधिकारियों की मिली भगत से अनेकों डिपो होल्डरों द्वारा मिट्टी का तेल अनाज व दालें कालाबाज़ारी में बेचे का समाचार मिला है। प्राप्त समाचार अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा के करनाल स्थित कार्यालय में कार्यरत निरीक्षक अपनी बन्धेज लेकर आंखें मूंदे रहते हैं और आंखे मूंदे ही डिपो होल्डरों का डेली रजिस्टर प्रमाणित करते रहते हैं जिस कारण कार्ड धाराकों के चिल्लाने का भी इन पर असर नहीं होता। अनेकों डिपो होल्डर ऐसे हैं जिनके पास बोगस बीपीएल राशन कार्डों की भरमार है और यह सब विभाग अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है। नियमानुसार डिपो होल्डरों के विरुद्ध खाद्य एवं वस्तु अधिनियम 1955 तहत कार्रवाई हो सकती है लेकिन करे कौन?

गौरतलब है कि एक बार 1988 में निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा में एक इश्तिहार जारी करके डिपो होल्डरों व जनता से अपील की थी कि अपनी इच्छा से बोगस राशनकार्ड जमा कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके बाद जो दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। लेकिन कार्रवाई क्या होनी थी? जिनकी रगो में भ्रष्ट खून दौड़ रहा है भला वह ऐसा क्यों करे? चोर पकड़ने से पहले भागने का रास्ता बताने वाली कहावत चरितार्थ मशहूर हूई। उस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा के करनाल के अधिकारियों कर्मचारियों ने सरकारी खाना पूर्ति के लिये किसी डिपो होल्डर के पास 10 राशनकार्ड और किसी के पास 20 बोगस था करके काट दिये। जबकि तकरीबन हर डिपो के पास औसतन सैंकड़ों राशन कार्ड बोगस थे।

गत वर्ष एक सर्वे में बहुत से बीपीएल राशनकार्ड पाये गये लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राप्त सूचना अनुसार सर्वे भी पूर्णतया ठीक नही हुआ आज भी हज़ारों की संख्या में बोगस बीपीएल राशन कार्डो की भरमार है। जो सरकार से सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल दाले अनाज व गेहूं खरीद कर डिपो होल्डर बाज़ार किराना वालों को बेचकर सरकार को चूना लगा रहे हैं।

डिपो होल्डर अपनी दुकान खोलने का कोई समय व दिन फिक्स नहीं है जब मूड हो खोल कर बैठ जाते हैं जब मूड नहीं तो बन्द करके चले जाते हैं। ग्राहक राशन के लिये चक्कर काट-काट कर चले जाते हैं। जब मिट्टी का तेल दालें अनाज व गेहूं आदि डिपो पर आता है तो डिपो होल्डर राशन डिपो पर आने की सूचना नही देते। डिपो खोलते समय जो आ गया वह राशन ले गया जो रह गया वो रह गया। जो रह गया उनके कोटे का मिट्टी का तेल दालें अनाज व गेहूं आदि डिपो होल्डर डेलि रजिस्टर में चढाकर मार्कीट में महंगे दामों पर बेच कर कालाबाज़ारी कर रहे हैं यह सब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा के करनाल के अधिकारियों की मिली भगत के बिना नही हो सकता। सदर बाज़ार के एक उपभोक्ता ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि भंवर लाल डिपो होल्डर की कई शिकायतें हुई परन्तु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि शिकायत कर्ता को ही डिपो होल्डर तंग करने लगा उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सरपंच गुरलाल ने बताया कि गांव बालू के डिपो होल्डर सुशील कुमार ने 240 राशन कार्ड अपने पास रखे हुये है जिनका राशन आता है और रिकार्ड में चढा कर ब्लैक में बेचता है जिसकी शिकायत 12.6.14 को फूड एण्ड सप्लाई विभाग को की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि करनाल में सड़कों बरामदों पर फुटपाथों पर जगह-जगह चाय के खोखे रेहड़ियां व छोटे-छोटे टेबल लगा कर चाय का कारोबार कर रहे हैं जो इन्क्रौमैन्ट तो करते हैं साथ में गैर कानूनी रूप से कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की जगह घरेलू सिलेण्डरों का प्रयोग कर रहे है जिनसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मंथली बांध रखी है करनाल के एक समाज सेवी ने बताया कि पटेल कलॉथ मार्कीट के अंदर एक चाय वाले ने घरेलू सिलेण्डर अपने चाय के काऊन्टर के अंदर छिपा कर लगा रखा है जिसकी सूचना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दी जिसमें अधिकारियों को सूचना देने पर उनका एक ग्राहक और बढ गया कारवाई करने की बजाये उससे मंथली बांध ली।

तुर्की ब तुर्की

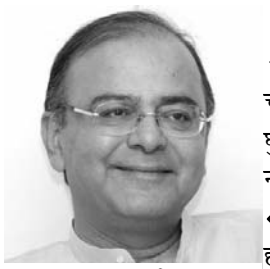

अरूण जेटली

"मनरेगा से मज़दूरी बढ गयी है और मज़दूर गायब हो गये हैं।"

हमारा कहना है :

◆ एक हरामखोर राजनेता ही देश के मज़दूरों को इस अंदाज़ में गाली दे सकता है। हमेशा से राज्यसभा के चोर दरवाजे से संसद में घुसने वाले अरूण जेटली तुमने इस बार अमृतसर की 'सेफ़' सीट से लोकसभा में घुसना चाहा और मोदी लहर के बावजूद चुनाव हार गये थे। यह बात और है कि पूंजीशाहों के विश्वस्त नमकहलाल होने की वजह से तुम्हें फ़िर भी वित्त मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया है।

◆ सभी का मानना है कि अगर अमृतसर से भाजपा ने अपने पुराने सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को उतारा होता तो वे सीट निकाल लेते। तो जेटली तुम्हारे लिये क्यों न यह कहा जाय कि जेटली की औकात तो बढ गयी पर भाजपा की एक सीट बलि चढ गयी। यही भाषा तुम्हारी समझ में आयेगी।

◆ तुम्हें अगर मनरेगा के मज़दूरों की मज़दूरी से इतनी ही परेशानी है तो एक दिन उनका जीवन जीकर देखो। उसके बाद देखते हैं तुम्हारी बेशर्मी का आलम कि क्या तुम 'मज़दूरी बढने-मज़दूर कम होने' का राग अलाप पाओगे।

◆ काश यह राग तुमने व तुम्हारे आका मोदी ने चुनाव से पहले अलापा होता! तब इस देश का मज़दूर भाजपा को वोट देने की ग़लती नहीं करता। क्या 'विकास' तुम जैसे हरामखोरों का ही होगा? मज़दूर इससे बाहर ही रखा जायेगा। आगामी चुनावों में वह तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने को व्याकुल हो रहा है।

वाहन पंजीकरण व लाइसैन्स बने लूट का जरिया

करनाल: (जे के पी के) सरकारी कार्यों को आसान बनाने के लिये तथा जनता की सीधी पहुंच के लिये प्रशासन ने अतिआवश्यक कार्यों को तहसील स्तर पर अनुमति दे दी ताकि आम जनता का कार्य शीघ्र व सुगम तरीके से हो सके। लेकिन बाबू संस्कृति के लोग़ों ने जनता की सरकारी कार्यों में अनभिज्ञता का लाभ उठाते हुये सरकारी कामों को जटिल बनाकर पैसा कमाने का जरिया बना डाला।

करनाल ज़िले में वाहन पंजीकरण व लाईसैन्स बनाने के लिये ३ स्थान तय किये गये हैं तथा वहां बैठे एस डी एम पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा कर परेशानियों से बच सके। करनाल में एच आर 05, असंध में एच आर 40, इन्द्री में एच आर 75, की सीरीज के पंजीकरण होते है। जहां भी कोई व्यक्ति रहता है उसी क्षेत्र में अपना लाइसेन्स व वाहन पंजीकरण करवा सकता है। सरकार ने प्रक्रिया भी एकदम सरल व सस्ती रखी है। लेकिन यहां बैठे कर्मचारी अधिकारियों की शह पर हर हाल में लूट मचाने में लगे हुये है। यहां तक कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में जिस काम की फ़ीस मात्र कुछ सौ रुपये बतायी गई उस काम के लिये हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं। कब और कितने देने पड़ेंगे वहां पर बैठने वाले अधिकारी पर निर्भर करता है वहां बैठा अधिकारी काम की तर्त्पता व काम कराने वाले की अच्छी हैसियत देख कर अधिक भी मांग कर लेता है। एक्ट में एक लाईसेन्स की फीस मात्र 30 रुपये है लेकिन ये भी 800 से कम में नहीं बनता और अगर दलाल बीच में पड़ गया तो उसकी फीस जुड़ जायेगी तब खर्चा होगा 3000 के आसपास। एक ग्राहक ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि उसका मेडिकल में कलर ब्लाईण्ड होने के कारण मेडिकल में फेल हो गया परन्तु एजेन्ट ने कहा कि सुपरिटैन्टड से सांठ-गांठ है 500 रुपये और दे दो कलर ब्लाईण्ड भी पास करवा देगा। खोजबीन से पता चला कि एजेन्ट कोआवेदक के पास ऐसा कोई भी फार्मूला नही कि वह पता कर सके कि असली खर्चा क्या है और कितना पैसा ठगा गया।

एस डी एम कार्यालयों में इसे आसान बनाने के लिये एक गैर सरकारी सुविधा जनता को दे दी जिसे सम्मानित भाषा में एजेन्ट व दूसरी भाषा में दलाल कहा जाता है। एस डी एम कार्यालय के आंख व कान है। इनका अपना एक नैट वर्क है जो मोटर डीजल के शौरूम व वर्कशाप, शहर के छुटभैये नेता व सामाजिक संस्थाओं व आर टी ए कार्यालय ट्रांसपोर्ट यूनियन, अधिवक्ताओं के सीधे सम्पर्क में रहते है। पुलिस वैरीफीकेशन करने वालों की जांचकर्ताओं का पूरा ब्यौरा इनके पास रहता है तथा कोई भी काम इनके फ़ोन करने पर ही हो जाता है।

इस कार्य में भारी पैसा चलता है लेकिन पूरा दिन कोई भी लेन देन नही होता लेकिन अगर किसी एजेन्ट की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की कार्यवाही की जांच की जाये तो प्रति दिन हज़ारों रुपये का लेन देन होता है। जिसमें एक साधारण रजिस्ट्री कलर्क, लाईसेन्स कलर्क से लेकर उच्चाधिकारी व पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। प्रत्येक अधिकारी की ए सी आर एक एजेन्ट के पास होती है जिसे वे आपसी भाषा में औकात बोलते है। इसीके अनुसार पैसा चलता है। अगर एस डी एम कार्यालय या अन्य कार्यालय का कोई काम आपको पड़े और आप सीधे कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां बैठे क्रमचारी समझेंगें कि या तो आप ऊंची पहुंच वाले है या मूर्ख। अगर आप पहुंच वाले हैं तो आपको चक्कर तो लगाने ही पड़ेगें। फ़िर कलर्क कई फारमैलटियां पूरी करवाने लगते हैं बेहतर होगा कि आप एजेन्ट की सुविधा का सहारा ले तो अपने आप ही फारमैलटियां पूरी करेंगे अन्यथा जरूरत ही नही होती।

करनाल में तीन उच्च स्तर के एजेन्ट है जो लगभग हरियाणा स्तर पर काम कर रहे हैं जिनका अपना कार्यालय किसी अधिकारी के कार्यालय से कम नहीं जहां पर आपको ट्रेनिंग प्रमाण पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र नोटरी पब्लिक, व स्टाम्प पेपर व जरूरत के लिये सभी कागजात मिल जायेंगे। आपको केवल निर्धारित समय पर केवल कम्प्यूटर में फोटो खिचवाना है। बाकी पैसा दो और काम हो गया। एस डी एम सिर्फ एक बात की गारन्टी सभी से लेता है कि कोई गलत काम न हो ताकि इज्जत बची रहे।

एजेन्टों की फाईल उसके अपने दफ़्तर में तैयार होती है जो किसी खास टाईम पर सुपरीटेंडन के कमरे में पहुंचती है तथा कर्मचारियों द्वारा अधिकारी के निवास पर अधिकारी पूरा सिगनल मिलने पर हस्ताक्षर करता है उसके बाद सीधा फ़ाइल एजेन्ट को दे दी जाती है। परन्तु ग्राहक व एजेन्ट में प्राय: झगड़ा रहता है कि पैसा दो साहब साईन नही कर रहा। इन एजेंटों ने लाने ले जाने के लिये आगे लड़के रखे हुये है जिन्हें स्टाफ़ कहा जाता है ये एकदम चुस्त-दुरूस्त होते है तथा कार्यालय की छोटी से छोटी हरकत व इशारा समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। कार्यालय में किस नम्बर से सम्बन्धित फाईल कहां पर है, इन अनुभवियों को पता होता है।

असल में पूरा करोबार इन्हीं के हाथों चलता है सभी सरकारी नियम व फ़ीस इनकी टिप्स पर है। एक एजेंट के पास पूरी जानकारी होती है कि साहब किसको किस सीट पर बैठायेगा और अगर कोई अड़चन पैदा करे तो सायंकाल की मीटिंग में उसकी सीट बदल दी जाती है। इसी डर से कर्मचारी प्राय: एजेन्टों को सलाम करते है। इस संवाददाता ने एक एजेंट से पूछा कि आपका काम कैसे चल रहा है तो उसने बड़े सहज भाव से कहा कि इतना सरकार कर्मचारियों को नहीं देती जितना हम इनको दे रहे है।

सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक मद में एक निर्धारित फीस लिखी गई है लेकिन एजेंट वहां बैठे-बैठे अधिकारी की ऐ सी आर के हिसाब से पैसा लेते हैं।